जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 135 प्रभात जालोर, शुक्रवार 22 अगस्त, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

बाड़मेर के बहुतप्रतिष्ठित नेता मेवाराम को कांग्रेस में पुनः ''एन्ट्री'' दिलाने के एक सूत्री अभियान में लगे गहलोत

मेवाराम के खिलाफ ''रेप'' व पॉक्सो के केस दर्ज हैं, तथा उनकी इन गतिविधियों के बारे में दो विडियो भी वायरल हुए थे, और बदनामी ही, मेवाराम के पार्टी से निष्कासन का कारण बनी थी

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 अगस्त। अमीन खान की कांग्रेस में वापसी के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मेवा राम जैन को भी कांग्रेस पार्टी में वापस लाने के लिए पूरी तरह जुट गए हैं।

मेवा राम जैन पर रेप और पॉक्सो एक्ट के केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ दो वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। गहलोत अपने करीबी माने जाने वाले जैन को वापस लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं।

ऐसा माना जाता है कि इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी रंधावा। बताया जाता है कि डोटासरा ने कल रात अचानक दिल्ली का दौरा किया और आज सुबह उन्होंने रंधावा से उनके दिल्ली स्थित घर पर मुलाकात की।

- ऐसा माना जाता है कि गहलोत के अभियान में डोटासरा व राजस्थान में पार्टी के प्रभारी रंधावा भी पूरी मदद कर रहे हैं।
- बुधवार की रात को डोटासरा ने दिल्ली की यात्रा की व रंधावा के घर पर उनसे मंत्रणा की। कहा यह जा रहा है कि मंत्रणा व मंथन का विषय था, ''वोट चोरी'' पर कांग्रेस की आयोजित होने वाली रैली। पर मेवाराम की घर वापसी की योजना भी मंथन का महत्वपूर्ण अंग थी।
- हालांकि, अभी दिल्ली, गहलोत के प्रयासों पर ध्यान नहीं दे रही है, पर वे नेतागण, जो गहलोत सरकार के ''लाभार्थी'' थे, अभी भी कोशिश में हैं, कि किसी भी तरह उनका नेता गहलोत कुछ महत्वपूर्ण पद पाये ए.आई.सी.सी. में।

दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार यह चर्चा राजस्थान में 7 सितंबर से पहले होने वाली ''वोट चोरी रैली'' के बारे में थी। लेकिन, यही एकमात्र मुद्दा नहीं था।

सूत्रों का कहना है कि मेवा राम जैन की वापसी का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल था। हरिश चौधरी के कड़े विरोध के बावजूद (क्योंकि दोनों बाड़मेर से हैं), रंधावा भी जैन की वापसी में मदद कर रहे हैं।

पार्टी सूत्रों का मानना है कि जब एआईसीसी का राज्य प्रभारी (इस मामले में रंधावा) किसी खास गुट (अशोक गहलोत) का हिस्सा बन जाता है, तो पार्टी का नुकसान होता है और गुटबाज़ी बढ़ती है।

दिल्ली से गहलोत को फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन साफ है कि राजस्थान के कई नेता अब भी गहलोत के प्रति वफादार हैं, क्योंकि उनमें से कई उनके शासनकाल के दौरान बड़े लाभार्थी रहे हैं।

सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने

नयी दिल्ली, 21 अगस्त। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सक्षम

- गोलचा ने एसबी सिंह का स्थान लिया है। वे 1992 बैंच के आईपीएस हैं।

अधिकारी की मंजूरी से गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी। गोलचा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन भरा

नयी दिल्ली, 21 अगस्त। उप राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को यहां गठबंधन के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल

- पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं।

किया। रेड्डी सुबह संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राज्यसभा सचिवालय में महासचिव पी सी मोदी के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने यूक्रेन-रूस युद्ध पर अपनी ''भाषण बाजी'' बदली

इसका प्रमुख कारण है, रूस-अमेरिका की अलास्का में हुई मुलाकात के बाद भी रूस ने प्रस्तावित शांति प्रस्ताव पर कोई ठोस सहमति नहीं दिखाई

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प का यूक्रेन-रूस युद्ध पर रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अब उनकी भी यही राय बनने लगी है कि वास्तव में रुस शांति समझौता करने का इच्छुक नहीं है।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि यूक्रेन को घुसपैठ का जवाब देने में पिछली अमेरिकी सरकार की नीतियों ने बांधकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रक्षा टीम मजबूत है, लेकिन उसे आक्रामक कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस तरह जीत पाना मुश्किल हो जाता है, भले ही असंभव न हो। उनके बयान से लगता है कि वे रूस के बढ़ते हमलों के खिलाफ यूक्रेन द्वारा बड़े पैमाने पर जवाबी आक्रमण किए जाने का समर्थन कर रहे हैं। अलास्का शिखर बैठक के बाद रूस ने यूक्रेन पर और भी तेज़ हमले किए, लेकिन बैठक में रूस की ओर से किसी शांति समझौते की ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखी। ट्रम्प इस बात से निराश हैं कि उनके शांति प्रयासों को रूस ने नकार दिया। पुतिन ने ट्रम्प के त्रिपक्षीय बैठक (पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रम्प) के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बजाय रूस ने भविष्य की वार्ताओं के लिए और ज्यादा उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व की बात कही, जिसे सीधा पुतिन-ज़ेलेंस्की वार्ता को ठुकराने का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की काफी तारीफ की, तथा अमेरिका ने जेलैंस्की की प्रशंसा करते हुए कहा, अमेरिका ने (बाइडन प्रशासन ने) जेलैंस्की के हाथ बांध रखे थे, जिसके कारण यूक्रेन रूस के भीतरी इलाकों पर बम की वर्षा करने से रूका हुआ था।
- रूस ने यूक्रेन से बातचीत का स्तर ऊँचा ऊठाने के बारे में कहा, कूटनीतिक भाषा में इसे शांति वार्ता को स्वीकार न करने का बहाना माना जाता है।
- अमेरिका द्वारा यूक्रेन के योद्धाओं की युद्ध में भूमिका की सराहना करने को भी, रूस के प्रति रवैया बदलने का संकेत माना जाता है।
- पुतिन भी अपने जाल में खुद ही फंसते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सभी यूरोपियन देशों के संगठित होकर यूक्रेन के समर्थन में खड़े होने से पुतिन के पूरे यूक्रेन का अधिग्रहण करने के इरादों पर कुछ पानी सा फिर गया है।

लोकसभा का मानसून सत्र भारी हंगामे के बीच समाप्त

स्पीकर ओम बिड़ला ने निराशा जताते हुए कहा, 120 घंटे बहस होनी चाहिए पर 37 घंटे ही हो सकी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नयी दिल्ली, 21 अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने गुरुवार दोपहर 12:12 बजे लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने पूरे मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लगातार किए गए हंगामे की कड़ी आलोचना की।

अध्यक्ष के अंतिम वक्तव्य के दौरान भी विपक्ष ने उन्हें नहीं बख्शा और हंगामा जारी रखा। उन्होंने कहा कि सत्र में 120 घंटे चर्चा होनी थी लेकिन मुश्किल से 37 घंटे ही बहस हो सकी।

हालांकि दोनों सदनों में हंगामे और बहिर्गमन के बीच 15 विधेयक पारित किये गये। लोकसभा में पेश किये गये 14 विधेयकों में से 12 को सदन की मंजूरी मिल गयी जबकि उच्च सदन में 15 विधेयक पारित किये गये। किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की गिरफ्तारी और तीस दिन की हिरासत की स्थिति में उन्हें पदमुक्त समझे जाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक और उससे जुड़े दो अन्य विधेयकों को लोकसभा ने समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया।

- मानसून सत्र में पहले ही दिन से भारी हंगामा शुरू हो गया था, मतदाता सूची पुनरीक्षण व आपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा। इस हंगामे के बीच 15 विधेयक पारित किए गए।

सत्र की पूरी अवधि के दौरान एकजुट विपक्ष ने सरकार को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी तथा उसे वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से घेरा और इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर दोनों सदनों में कार्यवाही में निरंतर व्यवधान डाला। विपक्ष ने सत्र के पहले दिन से ही ऑपरेशन सिंदूर और मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने पर सरकार ने हंगामे के बीच ही विधेयक पारित कराने की रणनीति अपनायी।

राज्यसभा को भी उपसभापति हर्षवर्धन ने पूर्वाह्न सत्र में दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। राज्यसभा में सदस्यों को 285 प्रश्न, 285 शून्यकाल विषय और 285 विशेष उल्लेख उठाने का अवसर था लेकिन केवल 14 प्रश्न, 7 शून्यकाल विषय और 61 विशेष उल्लेख ही वास्तव में लिए जा सके।

एसआई पेपर लीक में जयपुर ग्रामीण की महिला कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर, 21 अगस्त। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रामीण की स्पेशल ब्रांच में तैनात महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला कांस्टेबल ने लीक पेपर पढ़ कर लिखित

- उसने लीक पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा पास की थी पर इन्टरव्यू में फेल हो गई थी। उसकी बहन और एक चयनित एसआई पहले गिरफ्तार हो चुके हैं।

परीक्षा पास की थी, लेकिन इंटरव्यू में फेल होने से सलेक्ट नहीं हो सकी थी। महिला कांस्टेबल की मदद करने से लीक हुआ पेपर पढ़ कर एग्ज़ाम देने से परिचित का एसआई के पद पर सलेक्शन हुआ था। एडीजी (एटीएस व एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'संविधान निर्माता जानते थे कुछ कार्यों में टाइम लाइन जरूरी है और कुछ में नहीं'

'इसीलिए संविधान निर्माताओं ने 31 जगहों पर टाइम लाइन का उल्लेख किया है, जहां टाइम लाइन का उल्लेख नहीं है, तो वह जानबूझकर उठाया गया कदम है'

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21अगस्त। अगर कुछ राज्यपाल विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को लंबित रख रहे हैं, तो इसका हल राजनीतिक रूप से तलाशना चाहिए, न कि न्यायिक तरीके से - ऐसा भारत के सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रपति के संदर्भ मामले की सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा, जो विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की संविधान बैंच के समक्ष कहा कि हर समस्या का हल अदालत नहीं हो सकती।

- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय नहीं कर सकता। ''गवर्नर एक संवैधानिक पद है। इस मसले का राजनैतिक हल निकाला जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है।''
- सॉलिसिटर जनरल ने इस मसले पर प्रति प्रश्न किया, क्या संसद ऐसा कानून बना सकती है कि अगर किसी अपराधी का निर्धारित समय में ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो उसे बरी माना जाए? या फिर संसद यह कानून बना दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 600 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए।

बैंच द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मेहता ने कहा, व्यावहारिक उत्तर ये है कि अगर कोई राज्यपाल विधेयकों को लटकाए हुए है, तो इसका राजनीतिक समाधान मौजूद है। ऐसा हो भी रहा है, और हर जगह ऐसा नहीं है कि राज्य को तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्रतिनिधिमंडल जाता है और कहता है कि ये विधेयक लंबित हैं, कृपया राज्यपाल से बात कीजिए। कई बार फोन पर बात करके हल निकाला जाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल की संयुक्त बैठक होती है और गतिरोध समाप्त होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत उस पर समय-सीमा तय कर दे। सवाल यह है कि जब संविधान में कोई समयसीमा नहीं है, तब क्या अदालत उसे तय कर सकती है, चाहे उसका कोई औचित्य क्यों न हो? ऐसे मुद्दे कई दशकों से राज्य दर राज्य उठते रहे हैं। लेकिन जब राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व सामने आता है, तो संवैधानिक पदों पर आसीन लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं और राजनीतिक समाधान निकालते हैं। यही इस समस्या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्र.मंत्री मोदी को फोन किया

नयी दिल्ली, 21 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफ़ोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मैक्रों ने मोदी को टेलीफोन किया था।

बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों ने

- मैक्रों ने मोदी के साथ यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की।

हाल ही में वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हुई बैठकों के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने गाजा की स्थिति पर भी बातचीत की।

दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने और वर्ष 2026 को 'नवाचार वर्ष' के रूप में मनाने की संयुक्त प्रतिबद्धता की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयशंकर ने मॉस्को में रूस को भारत की 4 ट्रिलियन इकॉनमी, जो 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, का आकर्षण जताया

विदेश मंत्री जयशंकर के अनुसार, भारत में फर्टिलाइजर कैमिकल्स व मशीनरी का भारी मार्केट है, जिसे भरोसेमंद सप्लायर की जरूरत है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अगस्त। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हाल के मॉस्को में दिए गए बयान भारत की विदेश नीति में आ रहे एक गहरे बदलाव की ओर इशारा करते हैं। मॉस्को में एक बिज़नेस फोरम में बोलते हुए जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारत में और सक्रिय होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ रही है और भारत को खाद, रसायन और मशीनरी की भरोसेमंद आपूर्ति चाहिए, जिन क्षेत्रों में रूस एक मज़बूत साझेदार है।

ऊपरी तौर पर यह जयशंकर की तीन दिन की रूस यात्रा का सामान्य राजनयिक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की संभावित भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करना था। लेकिन असल संदेश यह था कि जैसे-जैसे अमेरिका भारत पर शुल्क और जुर्माने बढ़ा रहा है, भारत अपना रुख पूर्व की ओर, रूस और अप्रत्यक्ष रूप से चीन की ओर, कर रहा है।

जयशंकर ने रूस को आजमाया हुआ साथी बताया और कहा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण और शहरीकरण विदेशी कंपनियों के लिए बड़े अवसर खोलता है। उन्होंने कहा, ''इनमें से हर पहलू रुसी कंपनियों के लिए साझेदारों के साथ और गहराई से जुड़ने को निमंत्रण है।'' जयशंकर की यह अपील रुस को भरोसा दिलाने और अमेरिका को चेतावनी देने, दोनों का संकेत थी, कि दंडात्मक आर्थिक कदम भारत को वैकल्पिक नेटवर्क की तरफ और ज्यादा धकेल देंगे।

इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भारतीय सामान पर शुल्क 50 प्रतिशत तक दोगुना कर दिया है और साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदते रहने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। वॉशिंगटन का कहना है कि ये कदम भारत को रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ जोड़ने के लिए हैं। लेकिन असर उलटा हुआ।

- रूस को भी, भारत से यह व्यापारिक रिश्ता बहुत भा रहा है, क्योंकि भारत में विशाल ''कंज़्यूमर बेस'' है, तथा एनर्जी की मांग निरन्तर बढ़ रही है, तथा भारत ''नॉन डॉलर'' मुद्रा में व्यापारिक लेन-देन करने को तैयार व तत्पर है, और इससे पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाये गये व्यापारिक प्रतिबंध अपने आप ढीले पड़ जाते हैं।
- भारत को अभी भी चीन से गले मिलने के बारे में कुछ ''आपत्तियां'' हैं, पर रूस के बीच में आने से यह आपत्तियां भी कुछ नरम पड़ सकती हैं।
- अतः जयशंकर का रूस को भारत में ''इन्वैस्टमैंट'' और बढ़ाने का सुझाव, अभी तो तीनों देशों, रूस, चीन व भारत, के लिए ''विन-विन'' स्थिति है।

भारत और रूस दोनों ने इन जुर्मानों को ''छोटी सोच'' और ''रुकावट डालने वाला'' बताया।

भारत के लिए ये टैरिफ सिर्फ आर्थिक परेशानी नहीं हैं, बल्कि भरोसे में दरार है। भारत अब तक अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखता आया है, लेकिन अमेरिका की आक्रामक नीति ने यह संतुलन बिगाड़ दिया है। अब भारतीय नीति-निर्माता रूस को सिर्फ ऊर्जा और रक्षा सप्लायर नहीं, बल्कि एक बड़े यूरेशियाई गठजोड़, जिसमें चीन भी शामिल है, को जोड़ने वाले पुल के रुप में देख रहा है।

भारत का चीन से सीधा गठबंधन करने का ज्यादा मन नहीं है, क्योंकि, दोनों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक टकराव है। लेकिन अमेरिका की हरकतों के कारण भारत के लिए विकल्प कम होते जा रहे हैं। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए सस्ती ऊर्जा, खाद और तकनीक चाहिए। अगर अमेरिका इनपर रोक लगाता है तो भारत विकल्प खोजेगा, और ये अधिकतर विकल्प रूस और चीन में मिल सकते हैं।

जयशंकर द्वारा रूसी कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का आ ान, दरअसल आर्थिक निर्भरता में विविधता लाने का संदेश है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ऊर्जा, उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर में चीन और रूस दोनों की मौजूदगी भारत में बढ़े। हालांकि, भारत चीनी प्रभाव से सतर्क है, लेकिन रूस और चीन की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव के कारण भारत के लिए इन दोनों देशों से दूरी बनाए रखना कठिन हो जाता है।

रूस के लिए भारत की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिमी प्रतिबंधों से घिरे रूस को बड़े और स्थायी बाज़ार की ज़रूरत है। भारत के पास बड़ी आबादी, ऊर्जा की बढ़ती मांग और डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में लेन-देन की सुविधा है। भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर रूस न केवल पश्चिमी दबाव का असर कम करेगा बल्कि एशिया के शक्ति-समीकरण में अपना रोल और मजबूत करेगा।

इस स्थिति का सबसे बड़ा लाभ चीन को हो सकता है। रूस पहले ही चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और आर्थिक सहारा बन चुका है। अगर भारत-रूस व्यापार बढ़ा, तो उसका बड़ा हिस्सा चीनी नेटवर्क से होकर गुजरेगा। नतीजा यह होगा कि अमेरिका की रूस को अलग-थलग करने की कोशिशें यूरेशियाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)